

आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका

शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ

- सरकार जन सुविधाएँ उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी क्यों लें, इसपर वाद-विवाद करना।
- अपने इलाके के स्वास्थ्य केन्द्र के कामकाज पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना।
- आर्थिक गतिविधियों के नियमन में सरकार की भूमिका विषय पर चर्चा करना।

संबंधित सीखने का प्रतिफल

- पानी, बिजली, सड़क, साफ-सफाई जैसी—जन सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका की पहचान करते हैं।
- आर्थिक गतिविधियों के नियमन में सरकार की भूमिका का वर्णन करते हैं।

परिचय—

भारत एक विकासशील देश है जो आजादी के बाद के वर्षों में लगातार अपनी आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत है। आर्थिक असमानता राष्ट्र राज्य की सबसे बड़ी चुनौती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को 'जीवन के अधिकार' का आश्वासन देता है और जीवन के लिए मूलभूत जरूरत है—भोजन, वस्त्र, और आवास।

संविधान सभा के सदस्यों में मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड 'नीति-निर्देशक तत्वों' को भी जोड़ा है ताकि समाज में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। सब की खुशहाली में ही देश की आर्थिक उन्नति है।

पिछली कक्षाओं में आप सब आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ चुके हैं। परन्तु आर्थिक उत्थान की सबसे बुनियादी समस्या गरीबी है। गरीबी का सामान्य अर्थ है अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र और आवास) की भी पूर्ति करने में सक्षम होना। इसका सबसे प्रमुख कारण है—रोजगार के अवसर उपलब्ध न होना। जन समुदाय में अधिसंख्य वर्ग ऐसे भी हैं जो गरीबी के स्तर से भी नीचे जीवन बसर करने के लिए

मजबूर हैं। इन्हें 'गरीबी रेखा से नीचे' 'बी.पी.एल. (Below Poverty Line) के परिवार या समुदाय कहते हैं।

इन परिस्थितियों से जनता की सुरक्षा के लिए सरकार आम जन तक सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेती है।

(1) सही उत्तर चयन करें—

- (क) भारत एक विकसित/विकासशील देश है।
- (ख) सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त/अप्राप्त है।
- (ग) देश के सभी नागरिकों को अनन्त वश्यकताएँ होती हैं— हाँ/नहीं
- (घ) लोगों को जीविकापार्जन के समान/असमान अवसर प्राप्त हैं।
- (ङ. सार्वजनिक सुविधाओं को आमजन जन तक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है— हाँ/नहीं

उत्तर—(क) विकासशील देश, (ख) प्राप्त, (ग) नहीं, (घ) असमान, (ङ.) हाँ।

(2) निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए—

प्रश्न (क) गरीबी से आप क्या समझते ?

उत्तर—अनिवार्य आवश्यकताओं जैसे—भोजन, वस्त्र, आवास आदि को भी पूरा नहीं कर पाना ही गरीबी है।

प्रश्न (ख) हमारे संविधान में नीति-निर्देशक तत्वों को क्यों जोड़ा गया है ?

उत्तर—हमारे संविधान में नीति-निर्देशक तत्वों को इसलिए जोड़ा गया है ताकि समाज में सामाजिक आर्थिक सुधार लाया जा सकें।

प्रश्न (ग) हमें कौन-कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है ?

उत्तर—हम सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्राप्त है—

- (i) समानता का अधिकार
- (ii) स्वतंत्रता का अधिकार
- (iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार
- (iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- (v) सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार
- (vi) संवैधानिक उपचार का अधिकार

(vii) वर्तमान में 'शिक्षा के अधिकार' को भी जोड़ा गया है।

प्रश्न (घ) बी. पी. एल. के परिवार से क्या समझते हैं ?

उत्तर—गरीबी रेखा के नीचे (Below poverty line) का संक्षिप्त रूप बी. पी. एल. है। ऐसी आबादी जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में अक्षम होती है।

प्रश्न (ड.) 'सार्वजनिक सुविधा' से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर—'सार्वजनिक सुविधा' का अर्थ वैसी आधारभूत सुविधाओं से हैं जो देश के विकास एवं लोगों के जीवन-स्तर को उन्नत बनाने के लिए अनिवार्य हैं। जैसे—शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, आवास, परिवहन, सामाजिक सुरक्षा आदि।

जनसुविधाएँ—

जनसुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है, जो जिन्दा रहने के लिए जरूरी होता है। भारतीय संविधान में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति तक वह पर्याप्त जनसुविधाएँ उपलब्ध कराये।

किसी भी जनसुविधा की यह महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका इस्तेमाल बहुत सारे लागे कर करते हैं, साथ ही भविष्य में भी यह उसी रूप में उपलब्ध रहती है। उदाहरण के लिए कोई स्कूल या अस्पताल एक साथ बहुत से लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है।

इसी प्रकार किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति से बहुत सारे लोग लाभ लेते हैं। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पम्पसेट चलाने के लिए कर सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाले छोटे-मोटे घरेलू उद्योग धंधे आसानी से चला सकते हैं। सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई-लिखाई में आसानी हो जाती है। इस प्रकार किसी-न-किसी तरह से अधिकांश लोगों को फायदा होता है।

शिक्षा—

भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारन्टी देता है। भारत सरकार के द्वारा 2009 में सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कानून बनाया गया है। इस कानून के बनने से शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार बन गया है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में भी 14 वर्ष तक की आयु में बालकों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।

स्वस्थ और शिक्षित समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब शिक्षा स्त्री और पुरुष प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी लोगों तक अगर शिक्षा की पहुँच होगी तो सभी भेद-भाव भी कम होंगे। भारत में शिक्षा के विकास में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों की सहभागिता है। परन्तु निजी क्षेत्र के विद्यालयों में समाज के कुछ ही लोगों की पहुँच हो पाती है। क्योंकि यह प्रायः महँगी होती है। अतः ऐसे में सरकार का यह दायित्व होता है कि वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा सभी लोगों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना मध्याह्न भोजन, सर्वशिक्षा अभियान समग्र शिक्षा जैसी योजनाएँ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जाती हैं। सर्व-शिक्षा अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार द्वारा 2000-2001 में आरम्भ की गयी थी जिसका लक्ष्य जनसमुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।

आइयें जाने—

(1) रिक्त स्थानों की पूर्ति करें

- (क) भारत सरकार के द्वारा ई. में सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कानून बनाया गया।
- (ख) अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा वर्ष तक के बच्चों के लिए है।
- (ग) सभी स्त्री-पुरुष शिक्षित होंगे तभी हमारा देश होगा।
- (घ) सभी तक शिक्षा पहुँचाना दायित्व होता है।
- (ङ.) शिक्षा का अधिकार अब हमारा अधिकार बन गया है।

उत्तर—(क) 2009, (ख) 6-14 वर्ष, (ग) विकसित, (घ) सरकार, (ङ.) मौलिक।

(2) निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए

प्रश्न (क) कितने वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देना सरकार का दायित्व है ?

उत्तर—6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का।

प्रश्न (ख) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आमजन तक पहुँचाना किसका दायित्व है ?

उत्तर—गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आमजन तक पहुँचाना सरकार का दायित्व है।

प्रश्न (ग) सर्व-शिक्षा अभियान कब और क्यों आरम्भ की गई थी ?

उत्तर—सर्वशिक्षा अभियान 2000-2001 में आरम्भ की गयी थी जिसका उद्देश्य जनसमुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था।

प्रश्न (घ) शिक्षा की पहुँच सभी तक हो इसके लिए सरकार क्या-क्या कर रही है ?

उत्तर—सभी तक शिक्षा की पहुँच हो इसके लिए सरकार कई योजना कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना मध्याह्न भोजन, समग्र-शिक्षा जैसे—कई योजनाएँ संचालित कर रही है।

(3) हाँ/नहीं बतायें

(क) 6 – 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा पाना मौलिक अधिकार है—हाँ/नहीं

(ख) क्या अभी तक हम पूर्णतः शिक्षित समाज का निर्माण कर पाये हैं—हाँ/नहीं

(ग) कस्तूरबा गाँधी विद्यालय केन्द्र सरकार की योजना है—हाँ/नहीं

(घ) भारत में शिक्षा के विकास में सिर्फ सरकारी क्षेत्र का योगदान है—हाँ/नहीं

उत्तर—(क) हाँ, (ख) नहीं, (ग) हाँ, (घ) नहीं,।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य—

एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन और सामाजिक परिवेश से कुशल सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ होता है। साथ ही समाज और देश के विकास में उत्कृष्ट योगदान दे सकता है। इस प्रकार स्वास्थ्य व्यक्ति की अमूल्य निधि है।

विलियम के अनुसार—स्वास्थ्य, जिन्दगी को सर्वोत्तम ढंग से जीने एवं सेवा करने का गुण है।

हमारे समाज में एक कहावत स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाती है—“यदि धन खो गया कुछ नहीं खोया, यदि स्वास्थ्य खो गया तो कुछ खो गया, परन्तु यदि चरित्र खो गया, तो सब कुछ खो गया।”

स्वास्थ्य का महत्व न केवल मानव के लिए है, बल्कि समाज के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सफलतापूर्वक अपने अधिकारों व कर्तव्यों का पालन कर मनुष्य सभ्यता को स्वस्थ व जीवित रख पाता है। देश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें समय पर अच्छी व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए सरकार कई स्थान पर अस्पताल स्थापित करती है। विभिन्न रोगों से बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रम, प्राथमिक उपचार, कई निःशुल्क जाँच एवं दशाएँ उपलब्ध करायी जा रही है ताकि आम नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच हो सके और लोगों का स्वास्थ्य स्तर बेहतर हो सके। पोलियो उन्मूलन भी इसी तरह की एक योजना है। इसके अलावा गर्भवती

महिलाओं एवं शिशुओं तथ कक्षा 8 तक के बालकों को विभिन्न पोषण सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती है ताकि न केवल उनका समुचित शारीरिक विकास हो बल्कि उनमें रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा क्षमता भी समुचित स्तर तक विकसित हो सके।

गरीब कमजोर वर्गों की अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान करने के लक्ष्य से केन्द्र सरकार ने 23 सितम्बर 2018 को 'आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PM JAY) प्रारम्भ की है। इस योजना में देश में अगले 5 वर्षों में (2023 तक 1500 वेलनेस सेंटर स्थापित किये जाएँगे।

देश में कुपोषण को जल्दी एवं प्रगतिशील तरीके से समाप्त करने हेतु 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत की गई।

पेयजल एवं स्वच्छता—

शुद्ध और साफ जल का मतलब है कि जल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अशुद्धियों और रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं से मुक्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत करते हुए पेयजल स्वच्छता पर विशेष जोर दिया। जीवन के लिए पानी आवश्यक है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। दूषित पानी से दस्त, पेचिस, हैजा आदि संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर रहता है। भारत में दूषित पानी के कारण प्रतिदिन लगभग 1600 व्यक्तियों की मृत्यु होती है, उनमें से ज्यादातर पाँच साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित कर इन मौतों को रोका जा सकता है।

स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता जरूरी है। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। ये समाज में अच्छे व्यक्तित्व और प्रभाव को बनाने में मदद करता है। भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। भारत के 68% परिवार के पास पेयजल की सुविधाएँ और घर के भीतर शौचालय 36% परिवारों में ही उपलब्ध है। गाँवों में यह समस्या ज्यादा है। लोग खुले में शौच करते हैं। इसका कारण गरीबी एवं स्वच्छता के जागरूकता का अभाव है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कहीं-कहीं लोग पानी के लिए प्राकृतिक स्रोतों एवं निजी कुओं आदि पर निर्भर है। जबकि शहरों में जलापूर्ति पाइप लाइन के जरिये की जाती है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में शहरों की आबादी में अत्यधिक वृद्धि के कारण सभी को पर्याप्त एवं स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना एक प्रकार के चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। शहरों के जलापूर्ति की जवाबदेही नगर पालिका या नगर निगम की होती है।

पानी की समस्या के समाधान के लिए देश में विभिन्न नदियों पर बड़े-बड़े बाँध बनाए गए हैं, जो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती हैं। इसके कई लाभ हैं—

- (1) बाढ़ को रोकथाम
- (2) सिंचाई के लिए जलापूर्ति
- (3) जलविद्युत उत्पादन
- (4) घरेलू कामकाज के लिए
- (5) उद्योग के लिए उपयोगी
- (6) मत्स्य पालन
- (7) मिट्टी के कटाव के रोकथाम
- (8) पर्यटन केन्द्रों का निर्माण

आवास—

आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। सरकार द्वारा 1985 ई. में ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 'इन्दिरा आवास योजना' शुरू की गयी। इस योजना से अनेकों परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। अब इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) कर दिया गया है। इसकी शुरुवात 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना द्वारा पूरे भारत में शहरी स्थानों में गरीबों को कम लागत पर पक्का घर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य 2022, तक 'सभी के लिए आवास प्रदान' करना है। इस घर में स्वच्छ पानी, शौचालय की सुविधा और 24 घंटे बिजली की सुविधा भी उपलब्ध कराना है।

भीमराव अम्बेडकर आवास योजना—

झारखण्ड राज्य में 14 अप्रैल 2016 को संविधान के जनक भीम राव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के विधवाओं के लिए आवास योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अन्तर्गत लाभुकों को तीन किस्तों में राशि भुगतान का प्रावधान है।

परिवहन—

वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना हो या किसी भी बाजार का विस्तार हो सभी में परिवहन का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान में यातायात साधनों में रेल, सड़क, जल एवं वायु परिवहन शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। इन साधनों के विकास के लिए बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। अतः इसके विकास की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। हांलाकि सड़क

निर्माण में निजी क्षेत्रों की सहभागिता भी देखी जा रही है। रेलवे और वायु परिवहन को छोड़कर बाकी का विकास जहाजरानी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा होता है। वायु परिवहन के विकास की जिम्मेदारी नागर विमानन विभाग के जिम्मे है। कम दूरी के लिए सार्वजनिक परिवहन का महत्वपूर्ण साधन बस ही है। प्रायः बसों का परिचालन निजी व्यक्तियों के द्वारा होता है। कहीं-कहीं सरकार निजी लोगों के साथ साझेदारी में भी सड़क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती है। परन्तु तेजी से शहरीकरण के कारण शहरों में आवश्यक संख्या में बस उपलब्ध नहीं हो पाती है।

झारखंड सरकार के द्वारा सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी प्रणाली के अन्तर्गत द्रुतगामी वातानुकूलित डीलक्स बस सेवा की शुरूआत की गयी है। जो राँची से जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह एवं मंदिनीनगर के लिए चलती है। इसमें विस्तार की भी योजना है।

दिल्ली एवं मुंबई जैसे महानगरों में सरकार द्वारा मेट्रो रेल परियोजना के रूप में महात्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड के निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11000 करोड़ रुपये का खर्च किया गया है।



सामाजिक सुरक्षा—

वह सुरक्षा जो समाज, उचित सगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होनेवाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है, सामाजिक सुरक्षा है। ये जोखिमों में बीमारी, मातृत्व, आरोग्यता, बृद्धावस्था तथा मृत्यु है। भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई योजनाएँ समय-समय पर आरम्भ की गयी हैं।

सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य के अन्तर्गत निम्न तत्वों को सम्मिलित किया जा सकता है—

- (a) क्षतिग्रस्त व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करना।
- (b) क्षतिग्रस्त व्यक्ति के पुनरुत्थान का प्रयास करना।
- (c) खतरों की रोकथाम के लिए आवश्यक व्यवस्था करना आदि।

संगठित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों के लिए भविष्य निधि योजना सामाजिक सुरक्षा का ही एक अंग है।

	योजना का नाम	व्यवस्था-उद्देश्य
1.	अटल पेंशन योजना (2015)	असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन के दायरे में लाना
2.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015	सालाना 12 रुपये प्रीमियम दर पर दो लाख का बीमा
3.	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2015	सालाना 330 रुपये भुगतान पर 2 लाख की बीमा
4.	सुकन्या समृद्धि योजना 2014	बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना है।
5.	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2016	निर्धनता - रेखा से नीचे को महिलाओं की निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करना।
6.	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना	असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
7.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार को 35 किग्रा. चावल या गेहूँ देना।

सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता की जवाबदेही सिर्फ सरकार की ही क्यों होती है ?

सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता में ज्यादा पूँजी की आवश्यकता होती है, जबकि निजी क्षेत्र की कंपनियों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अगर इन सुविधाओं की उपलब्धता की जवाबदेही निजी क्षेत्र को दे दी जाए, तो इनकी पहुँच कुछ ही लोगों तक हो सकेगी। इनके शोषण की भी संभावना रहती है। एक लोकतांत्रिक सरकार का उद्देश्य जनकल्याण होता है, जो पूरा नहीं हो सकेगा। निजी कंपनियाँ ऊँची कीमत पर सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग इन सभी सुविधाओं से लाभान्वित नहीं हो पायेंगे। इन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। अतः किसी भी आधुनिक समाज के लिए यह जरूरी है कि लोगों को जीने के अधिकार का आश्वासन देता है। ऐसी स्थिति में जनसुविधाओं की उपलब्ध कराने की जवाबदेही सरकार के उपर ही होना चाहिए।

सरकार को जनसुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है ?

संसद में प्रत्येक साल सरकार बजट पेश करती है। जिसमें सरकार अपने विगत साल के खर्चों का ब्यौरा पेश करती है और आगामी वर्ष के व्यय की योजना की भी रखती है।

बजट में सरकार इस बात की भी घोषणा करती है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करेगी? जनता से मिलने वाला कर (Tax) सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल कर वह सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करती है। सरकार की आय के विभिन्न स्रोत हैं—

आयात-निर्यात कर (सीमा-शुल्क), केन्द्रीय उत्पादन कर, आय कर, निगम कर आदि। इसके अलावे सरकार कार्य करने के लिए विभिन्न स्रोतों से कर्ज भी लेती है।

केन्द्रीय सरकार के कर राजस्व का विभाजन	
उधार एवं अन्य देताएँ—20%	
निगमकर — 21%	
आयकर —16%	
सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सेवा कर एवं अन्य कर—31%	
अन्य कर —12%	

(केन्द्रीय बजट 2019-20)

यह भी जाने—

वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax, GST) हम सभी जो भी सामान खरीदते हैं उस सभी पर GST नाम का कर भरना पड़ता है। यह जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू की गयी है। यह एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। यह पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगने वाले विभिन्न तरह के केन्द्रीय और राज्य स्तरीय करों के स्थान पर लागू की गयी है। इसका उद्देश्य भारतीय बाजार को एकीकृत करना है। अर्थात् किसी भी सामान पर इसका दर पूरे देश में एक जैसा होता है। इससे अधिकांश वस्तुओं पर कुल कर का बोझ काफी कम हो जाएगा।

जानने योग्य शब्द	
परिवहन	Transport
स्वास्थ्य	Health
शहरी क्षेत्र	Urban Area
ग्रामीण क्षेत्र	Rural Area
स्वच्छता	Sanitation
जनसुविधा	Public Facility
शिक्षा	Education
सरकार	Government
पेयजल	Drinking water
टीकाकरण	Vaccination
बाढ़	Flood
बिजली	Electricity
पर्यटन	Tourism
आवास	Accommodation
सामाजिक सुरक्षा	Social security
कर	Tax

अभ्यास प्रश्न

(1) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

- शहरों ने से पेयजल की आपूर्ति होती है।
- के तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को निःशुल्क एल.पी.जी. कनेक्शन मुहैया कराया जाता है।
- जन सुविधाओं के उपलब्धता की जिम्मेदारी की होनी चाहिए।
- बहुदेशीय परियोजना से एक साथ कई मिलते हैं।
- स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गाँधी के जन्म दिवस को आरम्भ किया गया।
- जनसुविधाओं का इस्तेमाल में भी उपयोग में लाने के लिए उपलब्ध रहती है।

- (g) इन्दिरा आवास योजना का प्रारम्भ में की गई।
 (h) कामकाजी लोग अधिकतर की ही यात्रा करते हैं।
 (i) मेट्रो रेल परियोजना एवं में शुरू की गयी है।
 (j) सुकन्या समृद्धि योजना की समृद्धि से संबंधित है।
 (k) सरकार की आय का मुख्य जरिया होता है।
 (l) वस्तु एवं सेवा कर का उद्देश्य भारतीय बाजार को करना है।

उत्तर—(a) पाइपलाइन, (b) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, (c) सरकार, (d) लाभ, (e) 2 अक्टूबर, (f) भविष्य, (g) 1985, (h) बस, (i) दिल्ली एवं मुंबई, (j) बालिकाओं, (k) कर, (l) एकीकृत।

(2) सही उत्तर का चयन करें

- (a) इन्दिरा आवास BPL लाभुक परिवार के किस सदस्य के नाम से आवंटित होगा ?
 (क) किसी भी सदस्य के नाम से (ख) परिवार के मुखिया के नाम से
 (ग) किसी महिला सदस्य के नाम से (घ) केवल किसी पुरुष के नाम से
- (b) अन्त्योदय अन्न योजना के द्वारा निर्धनतम व्यक्ति को कौन सा लाभ प्रदान किया जाता है ?
 (क) रोजगार (ख) आवास ऋण एवं अनुदान
 (ग) रियायती दर पर खाद्यान्न (घ) कृषि अनुदान
- (c) केन्द्र द्वारा चलायी जाने वाली योजना 'सब के आवास' के द्वारा किस क्षेत्र में आवास उपलब्ध करायी जाती है—
 (क) ग्रामीण (ख) शहरी
 (ग) ग्रामीण एवं शहरी (घ) सभी को
- (d) मेट्रो रेल परियोजना किस महानगर में उपलब्ध नहीं है ?
 (क) कोलकाता (ख) चेन्नई (ग) दिल्ली (घ) राँची
- (e) GST क्या है—
 (क) आयकर (ख) वस्तु एवं सेवाकर (ग) निगम कर (घ) सीमा शुल्क

उत्तर—(a) ग, (b) ग, (c) ख, (d) घ, (e) ख।